

[2023] 2 एस. सी. आर 256

मोहिंदर सिंह (मृत) एल. आर. एस. और एक अन्य के माध्यम से

बी.

नारायण सिंह और अन्य

(सिविल अपील सं. 3828 2017 का)

14 मार्च, 2019

[अजय रस्तोगी, सी. टी. रविकुमार और

बेला एम. त्रिवेदी, जे. जे.]

दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957: एसएस। 2 (52) , 2 (61) , 502 , 507 (क) दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954-एस. एस. 3 (5) , 150 – दिल्ली विकास अधिनियम, 1957-ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान - अभिलिखित भूमिधर ने दिल्ली के एक गाँव में अपनी भूमि को एक पंजीकृत बिक्री विलेख के माध्यम से बेच दिया-उसने 1989 में बिक्री विलेख के माध्यम से अपनी भूमि का कुछ हिस्सा फिर से उत्तरदाताओं को बेच दिया और बाद में उनके नाम बदल दिए गए-अपीलकर्ताओं का मामला कि उक्त बिक्री विलेख को प्रतिवादी के पक्ष में निष्पादित करने से पहले, अपीलकर्ताओं ने विषय भूमि पर कब्जा कर लिया था-अपीलकर्ता ने कभी भी अपील दायर करके प्रतिकूल कब्जे का दावा करने वाले उत्परिवर्तन आदेश को चुनौती नहीं दी। 64 1954 के अधिनियम-उक्त उत्परिवर्तन के आदेश को वित्तीय आयुक्त द्वारा यह मानते हुए दरकिनार कर दिया गया था कि उक्त हस्तांतरण धाराओं का उल्लंघन था। 33 1954 के अधिनियम और आदेश दिया कि भूमि को गाँव सभा में निहित किया जाए-जिसे प्रतिवादी द्वारा चुनौती दी गई थी और रिट याचिका को खारिज कर दिया गया था-हालांकि, डिवीजन बेंच ने एक बार यू/एस अधिसूचना जारी करके यह निर्णय दिया। 507 (क) ग्रामीण क्षेत्र-विषय भूमि शहरीकृत है, यह ग्रामीण क्षेत्र नहीं रह जाता है और इसके द्वारा शासित होता है

1954 के अधिनियम की अगली कड़ी में प्रावधान और 1954 के अधिनियम के तहत कार्यवाही अपील पर नहीं थी, यह अभिनिर्धारित किया गया: 1954 के अधिनियम और 1957 के अधिनियम के प्रावधानों के सामंजस्य पर, एक बार यू/एस शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक अधिसूचना प्रकाशित की गई है। 507 (क) 1954 के अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं-इसके बाद, 1954 के अधिनियम के तहत लंबित कार्यवाही गैर-कानूनी हो जाती है और अपना कानूनी महत्व खो देती है-तथ्यों पर, पक्षों को पूर्ण न्याय देने के लिए, अपीलकर्ताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे प्रत्यर्थियों को सभी बाधाओं से मुक्त विषय भूमि का भौतिक कब्जा सौंप दें-भारत का संविधान-Art.142।

256 मोहिंदर सिंह (मृत) एल. आर. एस. और एक अन्य के माध्यम से। नारायण सिंह और अन्य

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,

पकड़ना: 1.1 प्रावधानों का संयुक्त अध्ययन स्पष्ट रूप से

यह इंगित करता है कि दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 ऐसे क्षेत्र को शामिल नहीं करेगा जैसा कि पहली बार में परिभाषित किया गया है जिसे नवंबर, 1956 के पहले दिन या उससे पहले नगर पालिका में शामिल किया जा सकता है। 'भूमि' जिसे यू/एस द्वारा परिभाषित किया गया है। 3 (13) यह उपबंध करता है कि धारा 23 और 24 को छोड़कर, ऐसी भूमि जो प्रयोजन के लिए धारित या अधिकृत है मत्स्य पालन और मुर्गी पालन सहित कृषि, बागवानी या पशुपालन से संबंधित और आगे शामिल हैं

दिल्ली शहर से सटे भवनों द्वारा कब्जा की गई भूमि का अपवर्जन जो दिल्ली नगर निगम की स्थापना से पहले आती है और अधिकार तय करके इस उद्देश्य के लिए भूमि नहीं है अधिनियम, 1954 के अध्याय II के तहत कार्यकाल धारकों के तहत पक्षों की। [पैरा 26] [268-एफ-जी]

1.3 अधिनियम की धारा 150 (3), (4) और (5) से संकेत मिलता है कि यदि गाँव सभा क्षेत्र को परिभाषित ग्रामीण क्षेत्रों में शामिल करना बंद कर दिया जाता है।

अधिनियम, 1957 में अधिनियम की धारा 507 के तहत अधिसूचना के आधार पर, गाँव सभा भंग हो जाएगी या यदि गाँव सभा क्षेत्र का एक हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में शामिल होना बंद हो जाता है

उपरोक्त, उस क्षेत्र के लिए गाँव सभा की अधिकारिता उस हिस्से के संबंध में समाप्त हो जाती है और उस हिस्से के लिए भंग हो जाता है या उस हद तक गाँव सभा का आकार ग्रामीण क्षेत्र में शामिल होने के कारण कम हो जाता है। [पैरा 27] [268-जी-एच; 269-ए]

1.4 अधिनियम, 1957 को मुख्य रूप से लागू किया गया है

विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं को दूर करने के लिए जनता द्वारा भी। धारा 2 (52) 'ग्रामीण क्षेत्रों' को परिभाषित करती है जो [2023] 2 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह दर्शाता है कि दिल्ली का वह क्षेत्र जो निगम की स्थापना से ठीक पहले दिल्ली जिला बोर्ड की स्थानीय सीमाओं के भीतर आता है, ग्रामीण क्षेत्र माना जाएगा, लेकिन इसमें उसका ऐसा हिस्सा शामिल नहीं होगा जो अधिसूचना यू/एस के आधार पर हो। 507 शहरीकृत घोषित किया जाता है और इसे 'ग्रामीण क्षेत्र' शब्द के तहत शामिल करना बंद कर दिया जाता है और धारा 2 (61) 'शहरी क्षेत्रों' को दिल्ली के उन क्षेत्रों के रूप में परिभाषित करती है जो ग्रामीण क्षेत्र नहीं हैं। [पैरा 29,30] [270-सी-ई]

1.5 एक बार सक्षम द्वारा जारी अधिसूचना होने पर

अधिनियम, 1954 के उस दायरे और दायरे की, किसी भी तरह से, अधिनियम, 1957 के प्रावधानों द्वारा अवहेलना नहीं की जानी चाहिए। [पैरा 31,32] [270 ई-एच]

1.6 दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 कहीं भी भूमि की प्रकृति में अंतर नहीं करता है चाहे वह ग्रामीण हो या शहरी, जैसा भी मामला हो। डी. डी. ए. अधिनियम, 1957 को स्वीकृत योजना के अनुसार और उसके सहायक मामलों के लिए दिल्ली के विकास के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया है। यदि डी. डी. ए. अधिनियम की धारा 2 (ई) के तहत परिभाषित 'विकास' शब्द पर विचार किया जाता है, तो यह स्पष्ट रूप से अधिसूचित करता है कि जिस क्षेत्र को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद धारा 12 के तहत विकास क्षेत्र घोषित किया गया है, उसे अधिनियम के दायरे में एक विकास क्षेत्र माना जाएगा और यह भूमि के निपटान के उद्देश्य के लिए अपने आप में एक पूर्ण संहिता है। धारा 2 (1) में 'भूमि' शब्द भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के संदर्भ में है। डी. डी. ए. अधिनियम केवल अधिनियम की धारा 7 के तहत अधिसूचित स्वीकृत मास्टर प्लान और क्षेत्रीय विकास योजना के अनुसार दिल्ली के विकास के उद्देश्य के लिए है और इसके सहायक मामलों के लिए इस तथ्य की परवाह किए बिना कि यह एल. आर. एस. और अन्य के माध्यम से एक मोहिंदर सिंह (मृत) है।

वी. नारायण सिंह और अन्य

ग्रामीण क्षेत्र या शहरीकृत जो विभिन्न उद्देश्यों के लिए है अधिनियम, 1954 और अधिनियम 1957 के प्रावधानों द्वारा। [पैरा 33,35] [271 ए-सी; 272-एफ-जी]

1.7 अधिनियम, 1954 और अधिनियम 1957 के प्रावधानों के सामंजस्य के बाद, एक बार अधिसूचना प्रकाशित होने के बाद शक्ति यू/एस। 507 (क) अधिनियम, 1957 के प्रावधान,

1954 आवेदन करना बंद करें। इसके बाद, अधिनियम, 1954 के तहत लंबित कार्यवाही गैर-कानूनी हो जाती है और अपना कानूनी अधिकार खो देती है। महत्व। [पैरा 36] [272-जी-एच]

1.8 उत्तरदाताओं ने 1989 में एक पंजीकृत बिक्री विलेख द्वारा एम (अभिलिखित भूमिधर) से विषय भूमि खरीदी और बाद में, उत्पत्तिवर्तन भी, एक समय में, उनके नामों में खोला गया था। बाद में, उन्हें 1990 में विषय संपत्ति पर कब्जा करने के लिए एक दीवानी मुकदमा दायर करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

सवाल करते हैं। रिकॉर्ड से पता चलता है कि कुछ दौर की मुकदमेबाजी के बाद, वित्तीय आयुक्त ने आदेश को रद्द कर दिया बाद में यह मामला दिल्ली उच्च न्यायालय की खंड पीठ के पास गया और यह अभिनिर्धारित किया गया कि एक बार धारा 507 (ए) के तहत अधिसूचना जारी करके ग्रामीण क्षेत्र का शहरीकरण हो जाने के बाद, यह अधिनियम, 1954 के प्रावधानों द्वारा शासित नहीं होगा। [पैरा 40,41] [273-जी-एच; 274-ए-बी]

1.9 उच्च न्यायालय की खंड पीठ के फैसले को बरकरार रखने के बाद भी यह उत्तरदाताओं को जाने के लिए एक नया जीवन देता है

इस तथ्य के बावजूद कि एम (भूमिधर) द्वारा उनके पक्ष में पंजीकृत बिक्री विलेख निष्पादित किया गया था, विषय संपत्ति का कब्जा लेने में आगे हैं, लेकिन वे अभी भी कब्जे से वंचित हैं और काउंटर में अपीलार्थियों का बचाव यह है कि वे प्रतिकूल कब्जे से विषय भूमि के कब्जे में हैं। साथ ही, यह न्यायालय यह भी दर्ज कर सकता है कि एम (भूमिधर) द्वारा प्रत्यर्थियों के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत बिक्री विलेख कभी भी चुनौती का विषय नहीं था और ऐसी कोई कार्यवाही न्यायालय में लंबित नहीं है। [पैरा 42] [274-बी-डी]

1.10 प्रत्यर्थियों के कहने पर दायर दीवानी मुकदमा

पिछले 32 वर्षों से लंबित विषय भूमि पर कब्जा करने के लिए अभी तक अपनी यात्रा शुरू नहीं की है और इसे उस व्यक्ति के साथ अन्याय का उपहास कहा जाता है जो निर्विवाद रूप से शीर्षक [2023] 2 एस. सी. आर. है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

धारक अभी भी संपत्ति का आनंद लेने में असमर्थ है। दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों में, अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए और पक्षों के साथ पूर्ण न्याय करने के लिए, अपीलकर्ताओं को निर्धारित अवधि के भीतर सभी बाधाओं से मुक्त विषय भूमि का भौतिक कब्जा प्रत्यर्थियों को सौंपने का निर्देश दिया जाता है। [पैरा 43,44] [274-डी-जी]

अन्य (1999) 3 एस. सी. सी. 331: [1999] 1 एससीआर 969-आयोजित अप्रयोज्य।

उमेद सिंह बनाम। सरकार. एन. सी. टी. दिल्ली और अन्य 1997 एससीसी ऑनलाइन डेल 842-अस्वीकृत।

श्रीमती. इंदु खुराना बनाम। ग्राम सभा और अन्य 2010

एससीसी ऑनलाइन डेल 1334-अनुमोदित।

मामला कानून संदर्भ

[1999] 1 एससीआर 969

अप्रयोज्य रखा गया

पैरा 38

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं. 3828

2017 से।

उच्च न्यायालय के 22.11.2012 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2008 के एल. पी. ए. सं. 591 में नई दिल्ली में।

राकेश द्विवेदी, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सिद्धार्थ गुप्ता, कुशल सरकार, आर. सी.

कौशिक, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए।

विकास सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता। , अनमोल चंदन, सुश्री दीपिका कालिया, ऋषि

कुमार सिंह गौतम, चंद्र प्रताप, आदित्य कौल, अरविंद राणा, वैष्णवी, बांके बिहारी, गुरमीत सिंह मक्कर, अधिवक्ता। शरणार्थियों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था रास्टोगी, जे।

1. फैसले और आदेश के खिलाफ तत्काल अपील का निर्देश दिया जाता है

दिल्ली उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने दिनांक 22 नवंबर, 2012 को यह अभिनिर्धारित करते हुए पारित किया कि एक बार दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 507 (ए) के तहत अधिसूचना जारी करके ग्रामीण क्षेत्र का शहरीकरण हो जाने के बाद (जिसे इसके बाद "अधिनियम 1957" के रूप में संदर्भित किया जा रहा है), यह दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 के प्रावधानों द्वारा शासित नहीं होगा।

(इसके बाद इसकी अगली कड़ी में "अधिनियम 1954" के रूप में संदर्भित किया जा रहा है और एल. आर. एस. और एक अन्य के माध्यम से मोहिंदर सिंह (मृत) वी।

नारायण सिंह और अन्य [अजय रस्तोगी, जे।]

अभिनिर्धारित किया कि अधिनियम, 1954 के तहत कार्यवाही पक्षकारों को उचित मंचों से पहले अपने दावों/विवादों को आंदोलन करने के लिए नहीं छोड़ रही थी, यह स्पष्ट करते हुए कि कानूनी रूप से सभी याचिकाएं उचित मंच के समक्ष पक्षकारों के लिए उपलब्ध होंगी।

2. अभिलेख से जो तथ्य प्रकट होते हैं, वे यह हैं कि एक मामन सिंह, जो भूमि का अभिलिखित भूमिधर था, व्यापक रूप से मापा जाता था।

4. यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि 10 फरवरी, 1995 के वित्तीय आयुक्त के आदेश, जिसमें यह कहा गया था कि "विवादग्रस्त भूमि को गाँव सभा में निहित करने का आदेश दिया गया था" को अपीलकर्ताओं द्वारा कभी भी चुनौती नहीं दी गई थी, जबकि प्रत्यर्थियों ने दिल्ली उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष 1995 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 670 दायर करके 10 फरवरी, 1995 के आदेश को चुनौती दी थी, जिसे 14 जुलाई, 2008 के फैसले द्वारा खारिज कर दिया गया था और यह प्रत्यर्थियों के कहने पर चुनौती का विषय बन गया था। 2008 .

5. उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने एक निष्कर्ष वापस किया कि एक बार 23 अप्रैल, 1982 की अधिसूचना अभ्यास में प्रकाशित की गई है

अधिनियम, 1957 की धारा 507 (ए) के तहत शक्ति का अधिकार जो स्पष्ट रूप से विचाराधीन विषय भूमि का शहरीकरण करता है और [2023] 2 एस. सी. आर. के दायरे में लाता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अधिनियम, 1957 के दायरे में, यह अब ग्रामीण क्षेत्र नहीं रह गया है, इसलिए अधिनियम, 1954 के तहत सभी कार्यवाहियां पक्षों को उचित मंचों के समक्ष अपने दावों/विवादों को इस स्पष्टीकरण के साथ आंदोलन करने के लिए छोड़ देती हैं कि सभी कानूनी याचिकाएं पक्षकारों के लिए उपयुक्त मंचों के समक्ष उपलब्ध रहेंगी, जिसे 22 नवंबर, 2012 के विवादित फैसले के तहत शिकायत के निवारण के लिए अपनाया जा सकता है, जो हमारे समक्ष अपील में चुनौती का विषय है।

6. इस संदर्भ में, यह ध्यान दिया जा सकता है कि उत्तरदाताओं नारायण सिंह और सोम दत्त ने अनिवार्य निषेधाज्ञा के लिए एक दीवानी मुकदमा दायर किया था सिविल संहिता के आदेश XXXIX नियम 1 और 2 के तहत एक आवेदन

अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान करने के लिए प्रक्रिया, 1908। अस्थायी अधिकारिता के स्तर पर मामला प्रतिवादियों के कहने पर दायर एक विशेष अनुमति याचिका में इस न्यायालय में गया, जिसे राजस्व अधिकारियों को चार महीने में मामले का फैसला करने के निर्देश के साथ 23 जनवरी, 1992 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था। तत्पश्चात, 2 सितंबर, 1992 के आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने संबंधित एस. एच. ओ. को अपीलार्थियों को कब्जा सौंपने का निर्देश दिया और इस न्यायालय के आदेश के अनुसार, अपीलार्थियों के पास विचाराधीन विषय भूमि का कब्जा है।

7. अपीलार्थियों के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री राकेश द्विवेदी के प्रस्तुत करने का मुख्य जोर यह है कि द्वारा पारित आदेश के अलावा

अपीलार्थियों की भूमि के अधीन, इसका समर्थन एस. डी. एम. द्वारा धारा 81 के तहत वर्तमान अपीलार्थियों को दिनांक 18 जनवरी, 1984 को जारी किए गए नोटिस से किया जा सकता है जो इंगित करता है कि अपीलार्थियों के कब्जे में है।

8. विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि एक बार जब मामन सिंह ने 9 मार्च, 1970 को भाई राम के पक्ष में पंजीकृत बिक्री विलेख द्वारा भूमि बेच दी थी और उसका कब्जा सौंप दिया था, तो उन्हें (मामन सिंह) लगातार बिक्री विलेख को निष्पादित करने का कोई अधिकार, स्वामित्व और हित नहीं था और वह विषय भूमि के उत्तरदाताओं को कब्जा नहीं सौंप सकते थे। इसके अलावा, अपीलार्थियों को सौंपे गए कब्जे को बरकरार रखा गया है।

9. विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि अधिनियम, 1954 और अधिनियम 1957 के समग्र दृष्टिकोण को लेने के बाद, अधिनियम 1957 की धारा 507 (ए) के तहत अधिसूचना जारी करके शहरीकरण की घोषणा के बाद भी, यह अधिनियम 1954 के प्रावधानों के तहत प्रदत्त पक्षों के अधिकारों को समाप्त नहीं करेगा। अधिनियम, 1957 के तहत कोई प्रावधान नहीं है जो अधिनियम की धारा 507 (ए) के तहत शहरीकरण की अधिसूचना जारी करने का सुझाव दे सकता है जो अधिनियम 1954 के प्रावधानों को स्वचालित रूप से समाप्त कर देता है। इसके अलावा, अधिनियम, 1954 की धारा 150 (3) में विशेष रूप से एल. आर. एस. और एक अन्य के माध्यम से मोहिंदर सिंह (मृत) के लिए प्रावधान है।

नारायण सिंह और अन्य [अजय रस्तोगी, जे।]

परिणाम जब पूरी गाँव सभा ग्रामीण क्षेत्र नहीं रह जाती है

10. विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि अधिनियम, 1954 एक ऐसा कानून है जो धारा 1 (2) के आधार पर भूमि सुधारों से संबंधित एक विशेष अधिनियम है जो पूरे दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश तक फैला हुआ है। अधिनियम, 1957 के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र इससे बाहर नहीं है। यह धारा 5 के दायरे में कार्यकाल धारकों और भूमिधर के अधिकारों का निर्माण करता है और ऐसे अधिकारों को विभिन्न तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है। अध्याय III के तहत, धारा सी भूमि के उपयोगकर्ता से संबंधित है और धारा डी भूमिधर और धारा ई द्वारा भूमि के हस्तांतरण से संबंधित है। हस्तांतरण से संबंधित है और धारा एफ विभाजन से संबंधित है। इस प्रकार, अधिनियम, 1954 भूमिधर और अन्य कार्यकाल धारकों के अधिकारों से संबंधित एक विशेष संहिता है।

11. विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि जहाँ तक अधिनियम, 1957 का संबंध है, यह वह अधिनियम है जो दिल्ली नगर निगम से संबंधित है। अधिनियम, 1957 में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह सुझाव दे कि इसका उद्देश्य विनियमन करना है।

क्षेत्र के शहरीकरण के बाद केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में भूमिधर का कार्यकाल अधिसूचित किया जाता है। चूंकि अधिनियम, 1957 का उद्देश्य स्वामित्व को नियंत्रित करना नहीं है।

कार्यकाल के दौरान, धारा 502 द्वारा विशेष रूप से यह प्रावधान किया गया है कि अन्य कानूनों की तत्काल अवहेलना नहीं की जानी चाहिए।

12. वास्तव में, विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि अधिनियम, 1954 अधिनियम, 1957 की धारा 507 (ए) के तहत शहरीकरण के बाद भी काम करना जारी रखता है और आगे प्रस्तुत करता है कि डिबीजन बेंच द्वारा वापस किया गया निष्कर्ष

विवादित निर्णय में उच्च न्यायालय कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है और इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किए जाने के योग्य है। उनके निवेदन के समर्थन में, विद्वान वकील ने ओम प्रकाश अग्रवाल और अन्य बनाम बतारा बेहरा और अन्य मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है।

13. विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने उमेद सिंह बनाम सरकार मामले में उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा व्यक्त किए गए पहले के विचार पर ध्यान नहीं दिया है। दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और अन्य 2 की और यह कि उच्च न्यायालय की पूर्ववर्ती खंड पीठ ने भी अधिनियम, 1957 और अधिनियम, 1954 की योजना पर विचार किया और यह निष्कर्ष निकाला है कि अधिनियम, 1957 की धारा 507 (ए) के तहत अधिसूचना जारी होने पर यह पक्षकारों के अधिकारों को समाप्त नहीं कर सकता है।

1 1999 (3) एस. सी. सी. 331

21997 एससीसी ऑनलाइन डेल 842 [2023] 2 एस. सी. आर

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अधिनियम, 1954 और दी गई परिस्थितियों में, इस न्यायालय द्वारा निर्णय में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है।

14. इसके विपरीत, उत्तरदाताओं के वरिष्ठ वकील श्री विकास सिंह ने प्रस्तुत किया कि उत्तरदाता नारायण सिंह और सोम दत्त

भूमिधर मामन सिंह से 4 मई, 1989 को एक पंजीकृत बिक्री विलेख द्वारा क्रमशः 2 बीघा 18 बिस्वास और 2 बीघा खरीदी गई। जहाँ तक विषय संपत्ति पर अधिकार, स्वामित्व और ब्याज का संबंध है, यह उत्तरदाताओं के पक्ष में निहित है। 4 मई, 1989 के पंजीकृत बिक्री विलेख पर भाई राम द्वारा कभी सवाल नहीं उठाया गया है, जिन्हें बाद के बिक्री लेनदेन से व्यथित व्यक्ति कहा जा सकता है।

अपीलार्थियों द्वारा आरोप लगाया गया। यहां तक कि अपीलकर्ताओं द्वारा प्रतिकूल कब्जे का दावा किया गया अधिकार भी एक कमजोर अधिकार है और कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है। इस संबंध में, दीवानी मुकदमा जो उनके कहने पर दायर किया गया है, व्यावहारिक रूप से एक गैर-स्टार्टर है क्योंकि वर्तमान अपील लंबित है, फिर भी अपीलार्थियों को विचाराधीन विषय संपत्ति पर कोई अधिकार, स्वामित्व और हित नहीं है।

15. विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि अधिनियम, 1954 और अधिनियम, 1957 की योजना को देखते हुए, सामंजस्य करते हुए, दोनों अलग-अलग क्षेत्रों में शासित होते हैं और एक बार अधिसूचना धारा 507 (ए) के तहत प्रकाशित हो जाने के बाद भूमि को शहरीकृत घोषित किया जाता है, जो तत्काल मामले में विवादित नहीं है, अधिनियम, 1954 के तहत लंबित उत्परिवर्तन कार्यवाही खड़ी होती है।

यह बंद हो गया क्योंकि भूमि ग्रामीण क्षेत्र के रूप में मौजूद नहीं है और इस प्रकार, उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा यह निष्कर्ष वापस करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है कि अधिनियम, 1957 की धारा 507 (ए) के तहत अधिसूचना के प्रकाशन के बाद सभी उत्परिवर्तन कार्यवाही बंद हो गई है।

16. विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि यह दिल्ली उच्च न्यायालय का सुसंगत दृष्टिकोण है और विवादित निर्णय के अलावा, धारा के तहत अधिसूचना जारी करने का यही सवाल और प्रभाव है

507 (क) अधिनियम, 1957 की जांच पहले उच्च न्यायालय द्वारा श्रीमती. इंदु खुराना बनाम ग्राम सभा और अन्य 3 जिस पर निर्णय लिया गया था

26 मार्च, 2010 में और अधिनियम, 1954 और अधिनियम, 1957 की योजना की जांच करने के बाद, यह निर्णय लिया गया कि एक बार जब अधिनियम, 1957 की धारा 507 (ए) के तहत अधिसूचना जारी करके ग्रामीण क्षेत्र को शहरीकृत घोषित कर दिया जाता है, तो अधिनियम, 1954 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

17. विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि मामले की उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा दो अलग-अलग लोगों द्वारा जांच किए जाने के बाद पीठों द्वारा बाद के निर्णयों में इसका लगातार पालन किया जा रहा है

3 2010 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 1334 मोहिंदर सिंह (मृत) श्रू एल. आर. एस. एंड अदर बी. नारायण सिंह और अन्य [अजय रस्तोगी, जे।]

18. विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि जहां तक वर्तमान उत्तरदाताओं का संबंध है, अधिकार, शीर्षक और हित होने के बावजूद 4 मई, 1989 के पंजीकृत विक्रय विलेख और 31 मई, 1989 को एक स्तर पर उनके नाम में परिवर्तन किए जाने के अनुसार, दी गई परिस्थितियों में, कम से कम अपीलकर्ताओं को विषय भूमि पर कब्जा रखने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है, हालांकि मुकदमा प्रत्यर्थियों के कहने पर दायर किया गया है और प्रस्तुत करता है कि यह न्यायालय न्याय के हित में मुकदमे की बहुलता से बचने के लिए प्रत्यर्थियों के पक्ष में कब्जा बहाल करने पर विचार कर सकता है।

19. हमने पक्षकारों के विद्वान वकील को सुना है और उनकी सहायता से अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अध्ययन किया है।

20. अभिलेख पर आया तथ्यात्मक मैट्रिक्स विवादित नहीं है।

दलों के बीच। विचार के लिए उठाए गए कानून का सवाल यह है कि एक बार जब अधिनियम 1957 के तहत अधिसूचना जारी करके ग्रामीण क्षेत्र का शहरीकरण हो जाता है, तो उसके बाद के अधिनियम, 1954 के प्रावधानों पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

21. हम प्रासंगिक प्रावधान के बारे में एक विहंगम दृष्टिकोण लेना चाहेंगे।

23. अधिनियम, 1954 की धारा 1 (2) का विस्तार पूरे केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तक है, लेकिन यह धारा में अधिसूचित क्षेत्रों पर लागू नहीं होगी। 1 (2) (क) अधिनियम, 1954 का, अर्थात् ऐसा क्षेत्र जो नवंबर, 1956 के पहले दिन से पहले हो या हो सकता है, किसी नगरपालिका या अधिसूचित क्षेत्र में शामिल किया जाए।

सुसंगत अधिनियमों के अधीन क्षेत्र।

24. अधिनियम, 1954 के प्रभाव और दायरे की सराहना करने से पहले अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों पर ध्यान देना उचित हो सकता है।

वे इस प्रकार हैं:

" 1. (I) इस अधिनियम को दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 कहा जा सकता है।

सी आरा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(2) यह पूरे केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तक फैला हुआ है, लेकिन इन पर लागू नहीं होगा

(क) वे क्षेत्र जो नवंबर, 1956 के पहले दिन से पहले पंजाब नगर निगम अधिनियम 1911 के प्रावधानों के तहत किसी नगर पालिका या अधिसूचित क्षेत्र में या छावनी अधिनियम के प्रावधानों के तहत छावनी में शामिल किए जा सकते हैं।

1924 ,

3. परिभाषाएँ। - इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा (1) से (4) की आवश्यकता न हो।

" (5) " दिल्ली नगर "से वे क्षेत्र अभिप्रेत हैं जो दिल्ली नगर निगम की स्थापना से ठीक पहले दिल्ली नगर पालिका, सिविल स्टेशन अधिसूचित क्षेत्र, पश्चिमी दिल्ली नगर पालिका और किला अधिसूचित क्षेत्र की सीमाओं में शामिल थे; (6) (12) तक।

(13) " धारा 23 और 24 को छोड़कर "भूमि" का अर्थ है कृषि, बागवानी या उससे संबंधित उद्देश्य के लिए धारित या कब्जा की गई भूमि। मत्स्य पालन और मुर्गी पालन सहित पशुपालन और इसमें शामिल हैं

(क) उसके निकट आने वाली इमारतें,

(ख) गाँव की आबादी,

(ग) ग्रीवलेण्ड्स,

(घ) गाँव के चरागाह के लिए भूमि या पानी से ढकी भूमि और सिंचनों और अन्य उपज या भूमि को उगाने के लिए उपयोग की जाती है।

लेकिन शामिल नहीं है देह शहर से सटे क्षेत्रों के क्षेत्रों में इमारतों द्वारा कब्जा की गई भूमि, जिसे मुख्य आयुक्त आधिकारिक राजपत्र में एक अधिसूचना द्वारा अधिग्रहण के रूप में घोषित कर सकता है;

150. (1) & (2)

(3) यदि दिल्ली नगर निगम अधिनियम में परिभाषित पूरे गाँव सभा क्षेत्र को ग्रामीण क्षेत्रों में शामिल करना बंद कर दिया जाता है,

1957 , उस अधिनियम की धारा 507 के तहत एक अधिसूचना के आधार पर, उस क्षेत्र के लिए गठित गाँव सभा वहां खड़ी होगी।

इस तरह के विघटन पर, एन. डी. ई. आर. सिंह (मृत) ने एल. आर. एस. और एक अन्य नारायण सिंह और अन्य लोगों के माध्यम से [अजय रस्तोगी, जे.]

(क) सभी चल और अचल संपत्तियाँ और उसमें निहित धन सहित किसी भी प्रकार और प्रकार के सभी हित।

गाँव सभा क्षेत्र निधि, जो ऐसे विघटन से ठीक पहले गाँव सभा में निहित थी, गाँव सभा द्वारा उपयोग किए गए, प्राप्त किए गए या प्राप्त किए गए किसी भी विवरण के सभी अधिकारों के साथ, केंद्र सरकार में निहित होगी।

(ख) किए गए सभी कर्तव्यों, दायित्वों और देनदारियों, किए गए सभी अनुबंधों और उनके द्वारा किए जाने वाले सभी मामलों और चीजों,

ऐसे विघटन से पहले गाँव सभा के साथ या उसके लिए होगा

माना जाता है कि किया गया है, प्रवेश किया गया है या नियोजित किया गया है

केंद्र सरकार के साथ या उसके लिए किया गया;

(ग) के कारण सभी दरें, कर, शुल्क, किराया और अन्य शुल्क

इस तरह के विघटन से तुरंत पहले गाँव सभा

केंद्र सरकार को देय माना जाता है;

(घ) गाँव सभा द्वारा या उसके विरुद्ध शुरू किए गए या स्थापित किए गए सभी मुकदमों, अभियोजनों और अन्य कानूनी कार्यवाही को संघ द्वारा या उसके विरुद्ध जारी या स्थापित किया जा सकता है।

भारत का;

(ई) इस अधिनियम के प्रावधान ऐसे गाँव सभा क्षेत्र में भूमि के संबंध में लागू होंगे, जो केंद्र सरकार के खंड (ए) में निहित भूमि नहीं हैं, इस संशोधन के अधीन रहते हुए कि

उसमें गाँव सभा और गाँव पंचायत के संदर्भ होंगे।

केंद्र सरकार के संदर्भ के रूप में समझा जाए;

(च) के खंड (ख) में किसी बात के होते हुए भी

धारा 1 की उप-धारा (2), धारा 84,85,86 ए और 87 के प्रावधान और इस अधिनियम से संबंधित कोई अन्य प्रावधान - व्यक्तियों का निष्कासन निहित भूमि के संबंध में लागू होगा

खंड (ए) के अधीन केंद्र सरकार

संशोधन कि उसमें गाँव सभा और गाँव पंचायत के संदर्भों को केंद्रीय के संदर्भों के रूप में माना जाएगा सरकार।

) यदि गाँव सभा क्षेत्र के केवल एक हिस्से को शामिल करना बंद कर दिया जाए

गाँव सभा के क्षेत्राधिकार में उपरोक्त ग्रामीण क्षेत्र

उस क्षेत्र के लिए प्रतिस्थापित उस भाग के संबंध में और ऐसे उपकरकर्ता पर, उप-धारा के खंड (ए) से (एफ) के प्रावधान समाप्त हो जाएंगे।

) उस भाग पर लागू होगा जैसे कि गाँव सभा [2023] 2 एस. सी. आर. थी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बनाना आवश्यक समझ सकते हैं।

(5) यदि एक गाँव सभा क्षेत्र का आकार एक के परिणामस्वरूप कम हो जाता है

इसका हिस्सा जैसा कि ऊपर कहा गया है, ग्रामीण क्षेत्रों में शामिल होना बंद हो रहा है।

और मुख्य आयुक्त की राय है कि का आकार

गाँव सभा क्षेत्र इसके अंतर्गत आने के लिए पर्याप्त बड़ा नहीं है

एक अलग गाँव सभा का अधिकार क्षेत्र, वह अधिसूचना द्वारा

सरकारी राजपत्र घोषणा करता है कि ऐसा गाँव सभा क्षेत्र,

अधिसूचना में निर्दिष्ट की जाने वाली तारीख से

वहाँ अलग गाँव सभा क्षेत्र और गाँव सभा का गठन किया गया।

के लिए भंग हो जाएगा और यह निर्देश दे सकता है कि उक्त क्षेत्र को एक या अधिक आस-पास के गाँव सभा क्षेत्रों में शामिल किया जाएगा, और उसके बाद

दिल्ली पंचायत राज अधिनियम, 1954 की धारा 3 के प्रावधान

(दिल्ली अधिनियम 1955 का 3), जहाँ तक हो सके, लागू होगा।

25. संदर्भित प्रासंगिक प्रावधानों का संयुक्त अध्ययन

इसमें ऊपर स्पष्ट रूप से इंगित किया गया है कि अधिनियम, 1954 ऐसे क्षेत्र को शामिल नहीं करेगा जैसा कि पहली बार में परिभाषित किया गया है जिसे नवंबर, 1956 के पहले दिन या उससे पहले नगर पालिका में शामिल किया जा सकता है। धारा 3 (13) के तहत परिभाषित 'भूमि' में प्रावधान है कि धारा 23 और 24 को छोड़कर, कृषि, बागवानी या पशुपालन से जुड़े उद्देश्य के लिए आयोजित या कब्जा की गई भूमि जिसमें मत्स्य पालन और कुक्कुट पालन शामिल है और इसमें अन्य श्रेणियाँ भी शामिल हैं जो भूमि का हिस्सा हैं, लेकिन साथ ही, इसमें दिल्ली शहर से सटे क्षेत्रों या बेल्टों में भवनों द्वारा कब्जा की गई भूमि शामिल नहीं है। 26. 'दिल्ली शहर' को अधिनियम की धारा 3 (5) के तहत परिभाषित किया गया है जो स्पष्ट रूप से उन क्षेत्रों को परिभाषित करता है जो

दिल्ली नगर निगम की स्थापना को दिल्ली नगर पालिका की सीमा में शामिल किया गया था। दिल्ली शहर से सटे भवनों द्वारा कब्जा की गई भूमि का पूरी तरह से बहिष्कार किया गया है जो इससे पहले आती है

27. साथ ही, अधिनियम की धारा 150 (3), (4) और (5) इंगित करती है कि यदि गाँव सभा क्षेत्र को ग्रामीण क्षेत्रों में शामिल करना बंद कर दिया जाता है अधिनियम, 1957 में अधिनियम की धारा 507 के तहत अधिसूचना के आधार पर परिभाषित, गाँव सभा भंग हो जाएगी या यदि गाँव सभा क्षेत्र का एक हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में शामिल नहीं किया जाता है, जैसा कि ऊपर कहा गया है, तो हिंडर सिंह (मृत) एल. आर. एस. और अन्य के माध्यम से।

नारायण सिंह और अन्य [अजय रस्तोगी, जे।]

उस क्षेत्र के लिए गाँव सभा का उच्चारण उस संबंध में समाप्त हो जाता है।

उस हिस्से पर और उसके लिए भंग हो जाता है या उस हद तक, गाँव सभा का आकार कम हो जाता है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में एक हिस्सा काटा जाना बंद हो जाता है जैसा कि ऊपर कहा गया है।

28. आइए हम अधिनियम, 1957 के प्रासंगिक प्रावधानों पर विचार करें।

एन. टी. उद्देश्य जो निम्नानुसार हैं:

" 2 (52) " "ग्रामीण क्षेत्रों" से दिल्ली के वे क्षेत्र अभिप्रेत हैं जो निगम की स्थापना से ठीक पहले इसके अंतर्गत स्थित हैं -

के तहत स्थापित दिल्ली जिला बोर्ड की स्थानीय सीमाएँ

पंजाब जिला बोर्ड अधिनियम, 1883 (1883 का पंजाब अधिनियम 20), लेकिन इसके ऐसे हिस्से को शामिल नहीं करेगा जो धारा 507 के तहत अधिसूचना, ग्रामीण क्षेत्रों में शामिल नहीं की जाएगी जैसा कि यहाँ परिभाषित किया गया है;

2 (61) " शहरी क्षेत्रों से दिल्ली के वे क्षेत्र अभिप्रेत हैं जो ग्रामीण नहीं हैं।

क्षेत्र;

502. अन्य कानूनों की अवहेलना नहीं की जानी चाहिए-इस अधिनियम में प्रावधान के अलावा, इस अधिनियम में निहित कुछ भी निगम या किसी नगरपालिका प्राधिकरण या किसी नगरपालिका अधिकारी या अन्य नगरपालिका कर्मचारी द्वारा किसी भी कानून की अवहेलना को अधिकृत करने के रूप में नहीं माना जाएगा।

507. ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में विशेष प्रावधान। — इसके बावजूद इस अधिनियम के पूर्वगामी प्रावधानों में निहित कुछ भी,

(क) सरकार के पूर्व अनुमोदन से निगम, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह घोषणा कर सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों का कोई भी हिस्सा उसमें शामिल नहीं किया जाएगा और ऐसी अधिसूचना जारी होने पर उस हिस्से को शामिल किया जाएगा।

शहरी क्षेत्रों में और उनका हिस्सा बनने के लिए;

(ख) सरकार के पूर्व अनुमोदन के साथ निगम, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा,

((i) ग्रामीण क्षेत्रों या उनके किसी भी हिस्से को इससे छूट दी गई है।

इस अधिनियम के प्रावधानों के बारे में जो वह उचित समझता है,

((ii) ग्रामीण क्षेत्रों में या उसके किसी भी हिस्से में कर, दर, शुल्क और अन्य शुल्क उन दरों से कम दरों पर लगाए जाते हैं जो -

जिन करों, दरों, शुल्कों और अन्य शुल्कों को शहरी क्षेत्रों में लगाया जाता है या ऐसे क्षेत्रों या हिस्से को इससे छूट दी जाती है।

ऐसा कोई कर, दर, शुल्क या अन्य शुल्क। "

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(ग) निगम गाँव सभा का भुगतान करेगा।

((i) गाँव सभा क्षेत्र में व्यवसाय, व्यापार, नियुक्ति और रोजगार पर कर की आय के बराबर राशि, जब और जब वह कर लगाया जाता है, और ((ख) उस क्षेत्र में भूमि और भवनों पर संपत्ति कर की आय के ऐसे हिस्से के बराबर राशि जो निगम द्वारा कटौती के बाद समय-समय पर निर्धारित की जा सकती है।

ऐसी आय से संग्रह की लागत।

29. अधिनियम, 1957 को मुख्य रूप से दिल्ली नगर निगम के प्रशासन के लिए एक समान निकाय रखने के लिए अधिनियमित किया गया है ताकि विभिन्न निगमों को समेकित किया जा सके। निकाय, स्थानीय प्राधिकरण, नगरपालिका मामलों की देखभाल करना और बेहतर प्रशासन के लिए केंद्रीकरण करना और विभिन्न प्राधिकरणों के साथ-साथ जनता द्वारा सामना की जा रही समस्याओं को दूर करना।

30. धारा 2 (52) 'ग्रामीण क्षेत्रों' को परिभाषित करती है जो दर्शाती है कि दिल्ली का वह क्षेत्र जो एक

दिल्ली जिला बोर्ड की स्थानीय सीमाओं के भीतर आने वाले निगम को ग्रामीण क्षेत्र माना जाएगा, लेकिन इसमें ऐसा हिस्सा शामिल नहीं होगा जिसे धारा 507 के तहत अधिसूचना के आधार पर शहरीकृत घोषित किया गया हो और इसे 'ग्रामीण क्षेत्र' शब्द के तहत शामिल करना बंद कर दिया गया हो और धारा 2 (61) 'शहरी क्षेत्रों' को दिल्ली के उन क्षेत्रों के रूप में परिभाषित करती है जो ग्रामीण क्षेत्र नहीं हैं।

31. इसे और सरल बनाने के लिए, एक बार जब धारा 507 (ए) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचना जारी की जाती है, जो है -

ग्रामीण क्षेत्रों के संबंध में एक विशेष प्रावधान, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों को अधिसूचना जारी होने पर उसमें शामिल नहीं किया जाएगा और उसके बाद शहरी क्षेत्रों में शामिल किया जाएगा और इसके संदर्भ में शहरी क्षेत्रों का हिस्सा होगा

अधिसूचना। धारा 507 का उपखंड (बी) और (सी) अधिनियम, 1957 के दायरे और दायरे में आने वाले ऐसे क्षेत्रों के लिए छूट देने या कर लगाने की प्रकृति से संबंधित है।

32. साथ ही, धारा 502 जिस पर अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने अधिक जोर दिया है, इसमें केवल यह प्रावधान है कि -

अधिनियम (अधिनियम 1957) का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह उस समय लागू किसी भी कानून की अवहेलना करता है और इस कारण से कि अधिनियम, 1954 के दायरे और दायरे की किसी भी तरह से अधिनियम, 1957 के प्रावधानों द्वारा अवहेलना नहीं की जानी चाहिए।

मोहिंदर सिंह (मृत) एल. आर. एस. और एक अन्य के माध्यम से। नारायण सिंह और अन्य [अजय रस्तोगी, जे।]

33. इस स्तर पर, यदि हम दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (इसके बाद इसे "डी. डी. ए. अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया जा रहा है) पर गौर करें, तो यह कहीं भी भूमि की प्रकृति में अंतर नहीं करता है, चाहे वह ग्रामीण हो या शहरी, जैसा भी मामला हो। डी. डी. ए. अधिनियम, 1957 को स्वीकृत योजना के अनुसार और उसके सहायक मामलों के लिए दिल्ली के विकास के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया है।

यदि हम डी. डी. ए. अधिनियम की धारा 2 (ई) के तहत परिभाषित 'विकास' शब्द पर विचार करते हैं, तो यह स्पष्ट रूप से सूचित करता है कि जिस क्षेत्र को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद धारा 12 के तहत विकास क्षेत्र घोषित किया गया है, उसे अधिनियम के दायरे में एक विकास क्षेत्र माना जाएगा और यह भूमि के निपटान के उद्देश्य के लिए अपने आप में एक पूर्ण संहिता है। धारा 2 (1) में 'भूमि' अभिव्यक्ति के संदर्भ में है -

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894।

34. अधिनियम, 1957 की प्रासंगिक धाराओं को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

" 2 (ड) "विकास क्षेत्र" से ऐसा कोई भी क्षेत्र अभिप्रेत है जिसे

धारा 12 की उप-धारा (1) के तहत विकास क्षेत्र;

2 (1) "भूमि" पद का वही अर्थ होगा जो इसमें दिया गया है।

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 3।

12. विकास क्षेत्रों की घोषणा और भूमि का विकास

वे और अन्य क्षेत्र।

(1) इस अधिनियम के प्रारंभ के तुरंत बाद, केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, दिल्ली के किसी भी क्षेत्र को इन उद्देश्यों के लिए विकास क्षेत्र घोषित कर सकती है।

इस अधिनियम के बारे में:

बशर्ते कि ऐसी कोई घोषणा तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि ऐसी घोषणा के लिए कोई प्रस्ताव केंद्र द्वारा निर्दिष्ट नहीं किया गया हो। सरकार प्राधिकरण और दिल्ली नगर निगम को निर्देश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों के भीतर या ऐसी आगे की अवधि के भीतर जो केंद्र सरकार अनुमति दे और इस प्रकार की अवधि के भीतर अपने विचार व्यक्त करने के लिए

निर्दिष्ट या अनुमत अवधि समाप्त हो गई है।

(2) इस अधिनियम में अन्यथा प्रावधान किए जाने के अलावा, प्राधिकरण किसी भी क्षेत्र में भूमि का कोई विकास नहीं करेगा या नहीं करेगा जो विकास क्षेत्र नहीं है।

(3) इस अधिनियम के प्रारंभ के बाद किसी भी क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति या व्यक्ति द्वारा भूमि का कोई विकास नहीं किया जाएगा या नहीं किया जाएगा।

निकाय (सरकार के एक विभाग सहित) जब तक, [2023] 2 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जहाँ वह क्षेत्र एक विकास क्षेत्र है, ऐसे क्षेत्र के लिए अनुमति

(1)

विकास प्राधिकरण से लिखित रूप में प्राप्त किया गया है

इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार;
जहाँ वह क्षेत्र विकास क्षेत्र के अलावा कोई अन्य क्षेत्र है,

((ख)

इस तरह के विकास के लिए अनुमोदन या मंजूरी संबंधित स्थानीय प्राधिकरण या इस संबंध में सशक्त या अधिकृत किसी अधिकारी या प्राधिकरण से लिखित रूप में प्राप्त की गई है, ऐसे प्राधिकरण को नियंत्रित करने वाले कानून द्वारा या उसके तहत किए गए प्रावधानों के अनुसार या जब तक कि ऐसा न हो।

प्रावधान किए गए हैं, जिसके अनुसार

अनुदान से संबंधित विनियमों के प्रावधान

दिल्ली (भवन संचालन नियंत्रण) अधिनियम, 1955 (1955 का 53) के तहत किए गए विकास के लिए अनुमति, और इस अधिनियम के प्रारंभ से तुरंत पहले लागू:

बशर्ते कि संबंधित स्थानीय प्राधिकारी [के अधीन हो सकता है

धारा 53 क के उपबंध उन विनियमों में संशोधन करते हैं

इस तरह के क्षेत्र में आवेदन।
(4) किसी भी क्षेत्र में किसी भी योजना के संचालन में आने के बाद

उस क्षेत्र में कोई विकास नहीं किया जाएगा या नहीं किया जाएगा।

जब तक कि ऐसा विकास भी ऐसी योजनाओं के अनुसार न हो।
(5) उप-धारा (3) और (4) में कुछ भी निहित होने के बावजूद, किसी भी विभाग द्वारा शुरू की गई किसी भी भूमि का विकास

प्रारम्भ होने से पहले सरकार या कोई स्थानीय प्राधिकरण यह अधिनियम उस विभाग या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा पूरा किया जा सकता है।

उन उप-धाराओं की आवश्यकताओं के अनुपालन के बिना।

35. जहाँ तक डी. डी. ए. अधिनियम का संबंध है, यह केवल इस उद्देश्य के लिए है

स्वीकृत मास्टर प्लान के अनुसार दिल्ली का विकास और

अधिनियम की धारा 7 के तहत अधिसूचित क्षेत्रीय विकास योजना और उसके सहायक मामलों के लिए चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरीकृत जो अधिनियम, 1954 और अधिनियम 1957 के प्रावधानों के तहत आने वाले विभिन्न उद्देश्यों के लिए हो।

36. अधिनियम, 1954 और अधिनियम के प्रावधानों में सामंजस्य स्थापित करने के बाद

1957 , हमारा विचार है कि एक बार अधिनियम, 1957 की धारा 507 (ए) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए अधिसूचना प्रकाशित हो जाने के बाद, अधिनियम, 1954 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। इसके बाद, अधिनियम, 1954 के तहत लंबित कार्यवाही अवैध हो जाती है और अपना कानूनी महत्व खो देती है।

मोहिंदर सिंह (मृत) एल. आर. एस. और एक अन्य के माध्यम से। नारायण सिंह और अन्य [अजय रस्तोगी, जे।]

37. हम डिवीजन बेंच द्वारा व्यक्त किए गए विचार को मंजूरी देते हैं

उच्च न्यायालय में श्रीमती. इंदु खुराना (ऊपर) जिसका बाद में उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा दिनांक 22 नवंबर, 2012 को दिए गए फैसले में पालन किया गया था।

38. जहां तक ओम प्रकाश अग्रवाल और अन्य (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय के फैसले का संबंध है, जिस पर अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने निर्भरता रखी है, पहली बार में, प्रासंगिक कानूनों के तहत ऐसी कोई अधिसूचना नहीं थी जिसमें भूमि को शहरीकृत घोषित किया गया हो। अधिनियम, 1957 की धारा 507 (ए) के तहत तत्काल मामले में प्रकाशित और विद्वान वकील द्वारा उठाई गई आपत्ति उड़ीसा भूमि सुधार अधिनियम, 1960 के दायरे और दायरे के संदर्भ में थी और प्रश्न था

क्या सुधार अधिनियम का उस भूमि पर कोई अनुप्रयोग है जो उड़ीसा भूमि सुधार अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के तहत शहर के मास्टर प्लान का एक हिस्सा है। उस संदर्भ में, इस न्यायालय द्वारा यह टिप्पणी की गई थी कि सुधार अधिनियम के प्रावधान कृषि या अन्य उद्देश्यों के संबंध में किस हद तक लागू होंगे। यह अदालत बहुत

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ओरिसा भूमि सुधार अधिनियम, 1960 की धारा 73 (सी) के दायरे और दायरे में शहरीकरण के लिए आरक्षित मामले में कोई अधिसूचना प्रकाशित नहीं की गई थी, जो हमारे विचार में, अपीलार्थियों के लिए कोई सहायता नहीं हो सकती है।

39. जहाँ तक दिल्ली उच्च न्यायालय की खंड पीठ के पहले के फैसले के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें

उमेद सिंह (उपरोक्त) के मामले में विवादित फैसले के तहत डिवीजन बेंच द्वारा गौर नहीं किया गया, सैद्धांतिक रूप से, हम उमेद में उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए विचार से सहमत नहीं हैं।

40. निष्कर्ष निकालने से पहले, हम यह देखना चाहेंगे कि उत्तरदाताओं ने 4 मई, 1989 को एक पंजीकृत विक्री विलेख द्वारा मामन सिंह (भूमिधर दर्ज) से विषय भूमि खरीदी थी और एक समय उत्परिवर्तन भी उनके नाम पर 31 मई, 1989 को खोला गया था। बाद में, उन्हें विचाराधीन विषय संपत्ति पर कब्जा करने के लिए वर्ष 1990 में एक दीवानी मुकदमा दायर करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

41. रिकॉर्ड से पता चलता है कि कुछ दौर की मुकदमेबाजी के बाद, वित्तीय आयुक्त ने आदेश [2023] 2 एस. सी. आर. द्वारा उत्परिवर्तन के आदेश को दरकिनार कर दिया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह मामला बाद में 10 फरवरी, 1995 को दिल्ली उच्च न्यायालय की खंड पीठ के पास गया और 22 नवंबर, 2012 के फैसले द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि एक बार जब ग्रामीण क्षेत्र का शहरीकरण अधिनियम, 1957 की धारा 507 (ए) के तहत अधिसूचना जारी करके किया जाता है, तो यह अधिनियम, 1954 के प्रावधानों द्वारा शासित नहीं होता है।

42. जिस बात ने इस न्यायालय को आश्चर्य किया वह यह है कि 22 नवंबर को उच्च न्यायालय की खंड पीठ के फैसले को बरकरार रखने के बाद भी,

2012, यह प्रत्यर्थियों को इस तथ्य के बावजूद विषय संपत्ति पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ने के लिए एक नया जीवन देता है कि 4 मई, 1989 को मामन सिंह (भूमिधर) द्वारा उनके पक्ष में पंजीकृत बिक्री विलेख निष्पादित किया गया था, लेकिन वे अभी भी कब्जे से वंचित हैं और प्रतिवाद में अपीलकर्ताओं का बचाव यह है कि वे प्रतिकूल कब्जे से विषय भूमि के कब्जे में हैं। साथ ही, यह न्यायालय यह भी दर्ज कर सकता है कि मामन सिंह (भूमिधर) द्वारा प्रत्यर्थियों के पक्ष में निष्पादित 4 मई, 1989 का पंजीकृत बिक्री विलेख कभी भी चुनौती का विषय नहीं था और ऐसी कोई कार्यवाही न्यायालय में लंबित नहीं है।

43. इस समय, यह हमें याद दिलाता है कि प्रत्यर्थियों के कहने पर दायर दीवानी मुकदमा विषय भूमि का कब्जा लेने के लिए

जो पिछले 32 वर्षों से लंबित है, उसने अभी तक अपनी यात्रा शुरू नहीं की है और इसे उस व्यक्ति के साथ अन्याय का उपहास कहा जाता है जो निर्विवाद रूप से स्वामित्व धारक अभी भी संपत्ति का आनंद लेने में असमर्थ है।

44. दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों में, संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत हमारी शक्ति का प्रयोग करते हुए और संविधान के साथ पूर्ण न्याय करने के लिए।

पक्षकारों, हम अपीलकर्ताओं को निर्देश देते हैं कि वे इस आदेश के पारित होने की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर प्रत्यर्थियों को सभी बाधाओं से मुक्त विषय भूमि का भौतिक कब्जा सौंप दें। यदि अपीलार्थी निर्धारित समय के भीतर कब्जा सौंपने में विफल रहते हैं, तो प्रत्यर्थियों के लिए संबंधित क्षेत्राधिकार वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट को आवेदन करने का अधिकार होगा और स्थानीय प्रशासन की सहायता से आवश्यक आदेश प्राप्त करने के बाद विषय भूमि का कब्जा लेने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि कब्जा 4 मई, 1989 के पंजीकृत बिक्री विलेख के संदर्भ में सौंपा जाना चाहिए, जिसे मामन सिंह (भूमिधर) द्वारा संबंधित उत्तरदाताओं के नाम पर निष्पादित किया गया है।

45. उपरोक्त शर्तों में लंबित दीवानी मुकदमे का निपटारा कर दिया गया है।

मोहिंदर सिंह (मृत) ने एल. आर. एस. और
एक अन्य के माध्यम से 275 बी. नारायण सिंह और अन्य [अजय रस्तोगी, जे।]

46. हम तत्काल अपील में कोई
सार नहीं पाते हैं। वही यहाँ ए है

पूर्व में वर्णित टिप्पणियों के साथ खारिज कर
दिया गया। कोई लागत नहीं।

47. लंबित आवेदन, यदि कोई
हों, का निपटारा कर दिया जाएगा।

निधि जैन (तमन्ना, एलसीआरए द्वारा सहायता
प्राप्त)